मनोज एच. मिश्रा

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(2013 **की सिविल अपील संख्या** 2969)

अप्रैल 09, 2013

[सुरिंदर सिंह निज्जर और एम.वाई.इकबाल, जे.जे.]

श्रम कानून - कदाचार - निष्कासन - औचित्य - अपीलकर्ता, कर्मचारी और ट्रेड यूनियन नेता, एक परमाणु ऊर्जा परियोजना में - भारी बारिश के कारण परियोजना में दुर्घटना - अपीलकर्ता ने एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर घटना के बारे में बताया और गंभीर खामियों को भी उजागर किया परियोजना के कामकाज और इसके लिए आसन्न खतरे के संबंध में परियोजना अधिकारियों की ओर से - अपीलकर्ता को इस आधार पर हटाया जाना कि उसने अनाधिकृत रूप से प्रेस को परियोजना से संबंधित आधिकारिक जानकारी दी थी; बयान दिया, जो परियोजना प्रबंधन की आलोचना या उसके अधिकारियों की ईमानदारी पर आक्षेप लगाने के समान था और प्रेस को परियोजना के साथ-साथ राज्य अधिकारियों के लिए शर्मिंदगी पैदा करने वाली एक समाचार कहानी

बनाने में सक्षम बनाया - अपीलकर्ता पर सजा दी गई - आयोजित : अनुपातहीन नहीं था - अपीलकर्ता ने बिना किसी औचित्य के निगरानीकर्ता की भूमिका निभाई - अपीलकर्ता की कार्रवाई केवल संगठन में कमियों को उजागर करने के लिए नहीं थी - अपीलकर्ता ने संगठन के भीतर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाकर निंदनीय टिप्पणियां कीं - ऐसे आरोपों में स्पष्ट रूप से एक पूरे प्रोजेक्ट की अखंडता पर संदेह की छाया डालने के अलावा पूरे संगठन पर हानिकारक प्रभाव - अपीलकर्ता का आचरण एक वास्तविक "व्हिसल ब्लोअर" के लिए आवश्यक उच्च नैतिक और नैतिक मानकों के अंतर्गत नहीं आता था - अत्यधिक संवेदनशील परमाणु संगठन के भीतर काम करने वाले कर्मचारी गोपनीयता की शपथ ली गई है और उन्हें गोपनीयता समझौता करना होगा - अपीलकर्ता इसे बनाए रखने में विफल रहा आवश्यकतानुसार गोपनीयता और विवेक के मानक - अपीलकर्ता के साथ कोई अन्याय तो दूर कोई गंभीर अन्याय भी नहीं हुआ।

श्रम कानून - विभागीय जांच - दोषी कामगार द्वारा प्रवेश - जांच की कार्यवाही बंद करना - हटाना - जांच को फिर से खोलने की याचिका - अपीलीय के साथ-साथ पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा खारिज - उच्च न्यायालय ने मामले को फिर से खोलने से इनकार कर दिया - अपील पर, आयोजित किया गया : एक बार जब जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता-अपराधी द्वारा की गई सशर्त स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तो

उसके लिए आरोपों से इनकार करने का विकल्प खुला था - लेकिन उसने प्रारंभिक में दर्ज किए गए अपने पहले के इनकार को दोहराने के बजाय, एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति करने का विकल्प चुना। सुनवाई - अनुच्छेद · 136 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग दोबारा खोलने के लिए नहीं किया जा सकता।

इस स्तर पर संपूर्ण मुद्दा - ऐसी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के गंभीर गर्भपात को रोकने में सक्षम बनाने के लिए आरक्षित है - इसका प्रयोग आम तौर पर तब नहीं किया जाता है जब उच्च न्यायालय ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया हो जो उचित रूप से संभव हो - तथ्यों पर, अपीलकर्ता किसी भी विकृति को प्रदर्शित करने में विफल रहा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय - अब उसे जांच अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति से मुकरने की अनुमति नहीं दी जा सकती - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136।

भ्रष्टाचार - रोकथाम - मुखबिर - "व्हिसल ब्लोअर" - कौन है - आयोजित: प्रत्येक मुखबिर को स्वचालित रूप से एक वास्तविक "व्हिसल ब्लोअर" नहीं कहा जा सकता है - "व्हिसल ब्लोअर" एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एक योद्धा के गुणों को रखता है - उसकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और प्रेरणा में संदेह के लिए बहुत कम या कोई जगह नहीं रहनी चाहिए - "व्हिसल ब्लोअर" कहलाने वाले व्यक्ति की कार्रवाई के लिए प्राथमिक प्रेरणा

किसी संगठन को शुद्ध करने के लिए होनी चाहिए - यह किसी कार्रवाई के लिए आकस्मिक या उपोत्पाद नहीं होना चाहिए · किसी परोक्ष रूप से या स्वार्थी उद्देश्य - तथ्यों पर, अपीलकर्ता-अपराधी ने "व्हिसल ब्लोअर" का दर्जा दिए जाने के मानदंडों को पूरा नहीं किया।

अपीलकर्ता सूरत, गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (KAPP) में एक श्रमिक था। वह केएपीपी के मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के महासचिव भी थे। भारी बारिश के कारण उक्त परमाणु ऊर्जा परियोजना में एक दुर्घटना हुई, जब बाढ़ का पानी इसमें घुस गया और परमाणु रिएक्टरों से सटे टरबाइन का 25 फीट से अधिक हिस्सा पानी में डूब गया।

अपीलकर्ता ने एक स्थानीय समाचार पत्र 'गुजरात समाचार' के संपादक को एक पत्र लिखा, जिसमें उक्त घटना के बारे में बताया गया और परियोजना के कामकाज और केएपीपी के लिए आसन्न खतरे के संबंध में अधिकारियों की ओर से गंभीर खामियों को भी उजागर किया गया।

प्रत्यर्थी अधिकारियों ने अपीलकर्ता को रखा। निलंबन के तहत, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था - क) अनाधिकृत रूप से प्रेस को संचारित करना, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना के संबंध में

आधिकारिक जानकारी; बी) बयान देना, जो परियोजना प्रबंधन या कास्टिंग की आलोचना के बराबर था।

इसके प्राधिकारियों की सत्यनिष्ठा पर आक्षेप; और ग) प्रेस संवाददाता के साथ संपर्क स्थापित करना और उसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना जो परियोजना में एक कर्मचारी के रूप में उसके कर्तव्य के दौरान उसके पास आई थी, और इस तरह प्रेस को परियोजना के बारे में शर्मिंदगी पैदा करने वाली एक समाचार कहानी बनाने में सक्षम बनाना परियोजना के साथ-साथ राज्य प्राधिकारियों को भी।

अपीलकर्ता ने जांच अधिकारी के समक्ष स्पष्ट रूप से अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। स्वीकारोक्ति के मद्देनजर, जांच अधिकारी ने जांच कार्यवाही बंद कर दी। अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध माने गये। जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को केएपीपी की सेवा से हटाने का आदेश दिया।

आदेश को अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा गया था। इसके बाद, आदेश को एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एलपीए को खंडपीठ ने खारिज कर दिया था. इन सभी आदेशों को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई थी।

वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता को दी गई सज़ा कदाचार के अनुपात से अधिक थी।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित किया गया :1. अपीलकर्ता द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के मद्देनजर, किसी भी पक्ष द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। एक बार जब जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता द्वारा की गई सशर्त स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उसके पास आरोपों से इनकार करने का विकल्प खुला था। लेकिन उन्होंने प्रारंभिक सुनवाई में दर्ज किए गए अपने पहले के इनकार को दोहराने के बजाय, एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति करने का विकल्प चुना। अपीलकर्ता को अब जांच अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति से मुकरने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जांच को फिर से खोलने की याचिका अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई है। इसके बाद एकल न्यायाधीश के समक्ष भी इस पर बहस नहीं की गई। समर्पण सज़ा की मात्रा तक ही सीमित था। एलपीए में, डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे को फिर से खोलने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस स्तर पर पूरे मुद्दे को फिर से खोलने के लिए अनुच्छेद 136 के तहत असाधारण

क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसी शक्ति इस न्यायालय को न्याय के गंभीर गर्भपात को रोकने में सक्षम बनाने के लिए आरक्षित है। आमतौर पर इसका प्रयोग तब नहीं किया जाता जब उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा दृष्टिकोण अपनाया हो जो उचित रूप से संभव हो। अपीलकर्ता एकल न्यायाधीश या उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों में कोई विकृति प्रदर्शित करने में विफल रहा है। [पैरा 27] (792-एफ-एच; 793-ए-बी)

2.1. यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता "व्हिसल ब्लोअर" के रूप में कार्य कर रहा था। यह रिकॉर्ड की बात है कि अपीलकर्ता केवल 12 वीं कक्षा तक शिक्षित है। वह न तो कोई इंजीनियर है और न ही परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कार्यप्रणाली का विशेषज्ञ है। एक अंदरूनी सूत्र होने के अलावा, अपीलकर्ता "व्हिसल ब्लोअर" का दर्जा दिए जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करता था। किसी व्यक्ति को "व्हिसल ब्लोअर" के रूप में स्वीकार किए जाने की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक यह है कि गतिविधि के लिए उसकी प्राथमिक मंशा सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी सार्वजनिक संगठन या प्राधिकरण की अवैध गतिविधियों को उजागर करते हुए, सार्वजनिक हित में गतिविधि की जानी चाहिए। अपीलकर्ता का आचरण उच्च नैतिक और नैतिक मानक के

अंतर्गत नहीं आता है जो एक वास्तविक "व्हिसल ब्लोअर" के लिए आवश्यक होगा। [पैरा 28,33) [793-सी; 797-सी-एफ]

2.2. अपीलकर्ता ने बिना किसी औचित्य के निगरानीकर्ता की भूमिका निभाई। वह केवल प्रचार चाह रहे थे। अखबार की रिपोर्टों के साथ-साथ अन्य प्रचारों ने निस्संदेह स्थानीय आबादी के साथ-साथ पूरे गुजरात राज्य में काफी दहशत पैदा कर दी। प्रत्येक मुखबिर को स्वचालित रूप से एक प्रामाणिक "व्हिसल ब्लोअर" नहीं कहा जा सकता है। एक "व्हिसल ब्लोअर" वह व्यक्ति होगा जिसमें एक योद्धा के गुण हों। उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और प्रेरणा में संदेह के लिए बहुत कम या कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि ऐसा व्यक्ति एक ही संगठन से है और उसे कुछ ऐसी जानकारी है जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। "व्हिसल ब्लोअर" कहलाने वाले किसी व्यक्ति की कार्रवाई की प्राथमिक प्रेरणा किसी संगठन को शुद्ध करना होना चाहिए। यह किसी गुप्त या स्वार्थी मकसद के लिए की गई कार्रवाई के लिए आकस्मिक या उपोत्पाद नहीं होना चाहिए। [पैरा 34] [797- जी एफ-एच;798-ए-बी]

2.3. अपीलकर्ता का कार्य केवल संगठन में कमियों को उजागर करना नहीं था। अपीलकर्ता ने संगठन के भीतर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए निंदनीय टिप्पणी की थी। इस तरह के आरोपों से पूरी परियोजना की अखंडता पर संदेह की छाया पड़ने के अलावा पूरे

संगठन पर स्पष्ट रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि अत्यधिक संवेदनशील परमाणु संगठन के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और उन्हें एक गोपनीयता समझौते में प्रवेश करना पड़ता है। अपीलकर्ता गोपनीयता और विवेक के मानक को बनाए रखने में विफल रहा, जिसे बनाए रखा जाना आवश्यक था। यह 'घोर अन्याय' का मामला नहीं है. अपीलकर्ता को दी गई सज़ा 'अपराध के प्रति इतनी असंगत नहीं है कि इस अदालत की अंतरात्मा को झटका लगे।' अपीलार्थी के साथ कोई अन्याय तो दूर कोई घोर अन्याय भी नहीं हुआ है। [पैरा 35, 36] [798-बी-ई, एफ-जी]

गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड और अन्य। बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा और अन्य। (1980) 2 एससीसी 593: 1980 (2) एससीआर 146- विशिष्ट।

रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य। (1987) 4 एससीसी 611: 1988 (1) एससीआर 512; परिवर्तन एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य। [2004 के डब्लू.पी.(सी) संख्या 93 में 2003 के डब्लू.पी.(सी) संख्या 539 के साथ सर्वोच्च न्यायालय का आदेश]; इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन बनाम आर.के. जैन (2010) 8 एससीसी 281 और आर.के. जैन बनाम भारत संघ (1993) 4 एससीसी 119: 1993 (3) एससीआर 802 - संदर्भित।

संदर्भित न्यायिक दृष्टांत:

1980 (2) एससीआर 146 ने पैरा 18 को distinguish किया

1988 (1) एससीआर 512 पैरा 20, 36 को संदर्भित करता है

(2010) 8 281 पैरा 21, 28 को संदर्भित किया गया

1993 (3) एससीआर 802 पैरा 30 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2969/2013

2007 के एलपीए नंबर 1041 और 1997 के एससीए नंबर 2115 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.07.2009 से

प्रशांत भूषण, शमिक संजनवाला, प्योली, कैलाश पांडे, के.वी. अपीलार्थी की ओर से श्रीकुमार।

प्रतिवादियों की ओर से प्रवीण एच. पारेख, सुमन यादव, रितिका सेठी, अभिषेक विनोद देशमुख (पारेख एंड कंपनी के लिए)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

सुरिंदर सिंह निज्जर, **जे.**

1. **अपील स्वीकृत.**

2. यह अपील अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 31 जनवरी के विद्वान एकल न्यायाधीश के 2007, 1997 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 2115 में फैसले की पुष्टि करते हुए 2007 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 1041 में दिए गए 14 जुलाई, 2009 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। 11 मई, 2010 को, इस न्यायालय ने सजा देने के प्रश्न तक सीमित नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय में, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने केवल एक ही तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ साबित हुए आरोपों और आरोपों को देखते हुए और अपीलकर्ता पर लगाया गया निष्कासन का जुर्माना कदाचार के अनुपात से बाहर है। हालाँकि, लेटर्स पेटेंट अपील में, अपीलकर्ता द्वारा एक मसौदा संशोधन पेश किया गया था जिसमें इस आधार पर सेवा से हटाने के आदेश को चुनौती देने की मांग की गई थी कि अपीलकर्ता द्वारा किए गए कृत्य कदाचार नहीं थे। संशोधन का आवेदन खारिज कर दिया गया.

3. हम सीमित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक तथ्यों पर बहुत संक्षेप में गौर कर सकते हैं कि क्या अपीलकर्ता पर लगाया गया दंड कदाचार के लिए आश्चर्यजनक रूप से असंगत है।

4. 14 अक्टूबर, 1991 को अपीलकर्ता, जिसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सूरत, गुजरात में काकरापार परमाणु

ऊर्जा परियोजना (केएपीपी) में ट्रेड्समैन/बी क्लास ।।। पद पर नियुक्त किया गया था। वैधानिक नियमों के अनुसार उन्हें दो साल के लिए परिवीक्षा पर रखा गया था। यह उनका मामला है कि परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, उन्हें 14 अक्टूबर, 1993 से स्थायी माना जाता है। इसके बाद, 17 दिसंबर, 1993 को, उन्हें केएपीपी के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के मान्यता प्राप्त संघ के महासचिव के रूप में चुना गया था। , काकरापार अनुमथक कर्मचारी संगठन कहा जाता है। अपीलकर्ता का दावा है कि परमाणु ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक (प्रत्यर्थी नंबर 2) के कहने पर 22 सितंबर, 1995 को उपरोक्त संघ की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने तक, उन्होंने महासचिव के रूप में कार्य किया। संगठन। वह एक लोकप्रिय संघ नेता थे जो हमेशा तीन-चौथाई से अधिक बहुमत से चुनाव जीतते थे। 3 मई, 1994 को उन्हें अन्य लोगों के साथ संरक्षित कर्मकार घोषित किया गया। उनका दावा है कि संघ के महासचिव के रूप में, वह बहुत सक्रिय थे और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा अतिरिक्त प्रयास करते थे कि संघ के सदस्यों की वास्तविक मांगों को उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाए। यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में, वह नियमित रूप से स्टेशन निदेशक, केएपीपी (प्रत्यर्थी संख्या 4) के संपर्क में थे। संघ की गतिविधियों के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता के प्रत्यर्थी संख्या 4 के साथ संबंध खराब हो गए। हालाँकि, अपीलकर्ता ने उत्तरदाताओं के साथ कामकाजी संबंध बनाए

रखा। अपीलकर्ता का यह भी दावा है कि मानसून के मौसम के दौरान 15 जून, 1994 की रात भारी बारिश हुई थी और काकरापार बांध में पानी खतरे के स्तर से ऊपर बढ़ गया था। परिणामस्वरूप, बांध अधिकारियों को बाढ़ द्वार खोलने पड़े। सामान्य परिस्थितियों में, काकरापार झील को बांध का पानी एक नहर के माध्यम से प्राप्त होगा जो एक इंटरलिंक है। झील के पानी का उपयोग उत्तरदाताओं के अधिकारियों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। हालाँकि, 15 जुलाई 1994 की रात यह बाढ़ का पानी था, जो काकरापार झील में घुस गया और देखते ही देखते प्लांट में भी घुस गया। अगली सुबह होने से पहले, परमाणु रिएक्टरों से सटे टरबाइन का 25 फीट से अधिक हिस्सा पानी में डूब गया था। दरअसल, पूरा रिकॉर्ड रूम और कंप्यूटर रूम पानी में बह गया। वह अलग, परमाणु कचरे वाले कुछ बैरल भी बाढ़ के पानी में बह गए। 16 जुलाई, 1994 को, प्रत्यर्थी अधिकारियों ने आपातकाल की घोषणा की, और निवारक उपाय करना शुरू कर दिया।

5. अपीलकर्ता का दावा है कि कई लोगों द्वारा सवाल उठाया जा रहा था कि बाढ़ के पानी को टर्बाइनों और संयंत्र के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने से क्यों और कैसे नहीं रोका जा सका। इसलिए 18 जून, 1994 को अपीलकर्ता ने संपादक, गुजरात समाचार, सूरत को उपरोक्त घटना के बारे

में गुजराती भाषा में एक पत्र लिखा। पत्र की एक अनुवादित प्रति विशेष अनुमति याचिका के अनुलग्नक: पी1 पर रखी गई है और इस प्रकार है:-

"दिनांक: 18.06.1994

सेवा में,

संपादक,

गुजरात समाचार,

सूरत।

16.06.94 को कांकरापार में पानी भर गया था, इस कारण कांकरापार में लगभग 25 से 30 फीट पानी भर गया था, इस कारण परमाणु केंद्र में बंद पड़ी मशीनें, यूनिट नंबर 1 बंद, कई मशीनें चली गईं पीछे, और यदि यही इकाई क्रमांक 1 चालू हालत में होती तो स्थिति बहुत गंभीर होती, इकाई क्रमांक 2 अभी चालू नहीं हुई है। 16.06.94 की रात को पाली माही योजना में पानी भर गया था, लेकिन विभाग के कुछ अभियंता जो रात को पाली में मौजूद थे, उन्होंने कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा, इस कारण पानी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता गया और स्थिति इतनी बदतर हो गई कि आपातकाल की घोषणा कर दी गई और कर्मचारियों को बाहर भेज दिया गया, जो कर्मचारी बचे थे उनके लिए खाने-

पीने की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई, कर्मचारी नेता मनोजभाई मिश्रा का कहना है कि यह सब गंभीर भ्रष्टाचार का नतीजा है। विभाग ने लाखों रुपये खर्च किए हैं और कई बड़ी नहरें बनाई गईं, लेकिन उनका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया इसलिए ....अपात्रता...फील्ड इंजीनियर अनुभाग के कारण हजारों रुपये खर्च किए गए और इमारत में स्थिति बहुत गंभीर और कारण थी। इस कारण मोटर, पंप, पाइपिंग पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन वह सब डूब गया है।

कर्मचारी नेता मनोजभाई मिश्रा ने कहा है कि विभाग में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किये गये हैं, जिसके कारण यह स्थिति बनी है. मनोजभाई मिश्रा ने आगे कहा है कि यह कोई कपड़ा मिल, चीनी मिल या कोई पेपर मिल नहीं है बल्कि यह भारत देश की एक बहुमूल्य संपत्ति है और यह एक परमाणु रिएक्टर है। मनोजभाई मिश्रा का कहना है कि काकरापार परमाणु केंद्र के संबंध में तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराई जाए और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो।

आपको धन्यवाद,

भवदीय,

एसडी/-

[मनोजभाई मिश्रा]

महासचिव कर्मचारी संघ"

6. अपीलकर्ता का कहना है कि उसने किसी भी आधिकारिक जानकारी का खुलासा नहीं किया जो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान प्राप्त हो सकती थी। उनका दावा है कि पत्र में बताए गए तथ्य सार्वजनिक जानकारी और सार्वजनिक चिंता का विषय थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि सभी समाचार पत्रों, राजनेताओं, विधान सभा के सदस्यों और अन्य नागरिकों ने परमाणु परियोजना की सुरक्षा के संबंध में और उक्त घटना कैसे घटित हो सकती है, इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की। अपीलकर्ता ने जलजमाव से संबंधित तथ्य बताये थे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो. अपीलकर्ता 22 जून, 1994 के समाचार पत्र अनुमुक्ति पर आधारित है जिसका शीर्षक है "ईमानदारी और साहस की कीमत चुकाना"। यह लेख बताता है कि हालाँकि सौभाग्य से कोई बड़ी आपदा नहीं हुई, लेकिन घटना ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र अधिकारियों की सुरक्षा के प्रति ढीले रवैये को उजागर किया। लेख कुछ गंभीर

अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। अनियमितताओं को इंगित करने के बाद, लेख समाप्त होता है: -

> “यह सब देश में परमाणु ऊर्जा के डिजाइनरों, संचालन और नियामकों की ओर से आपराधिक लापरवाही को दर्शाता है और फिर भी किसी को भी कोई प्रतिकूल परिणाम भुगतने की संभावना नहीं है। श्री मनोज मिश्रा को छोड़कर कोई नहीं – वही व्यक्ति जिसने सीटी बजाई थी”।
>
> xx xx xx
>
> “प्रेस से बात करने के अपराध में मिश्रा को तुरंत काम से निलंबित कर दिया गया था और घटना के पांच महीने बाद भी उनका निलंबन आज भी जारी है। जबकि वे सभी लोग जिन्होंने कर्तव्य के प्रति एकमात्र लापरवाही प्रदर्शित की, वे मजे से चलते रहे, एक व्यक्ति जिसने देश के हित को अपने स्वार्थ से ऊपर रखा, उसे दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में भुगतना पड़ा कि परमाणु प्रतिष्ठान में केवल 'लीक' ही मायने रखती है। ये प्रामाणिक जानकारी के लीक हैं।”

7. अपीलकर्ता का दावा है कि 22 जून, 1994 को समाचार प्रकाशित होने के बाद ही बाहर के लोगों और यहां तक कि बॉम्बे में परमाणु प्रतिष्ठान ने भी इस घटना का संज्ञान लिया। स्टेशन अधीक्षक सूरत पहुंचे और सूरत के जिला कलेक्टर के साथ एक बयान जारी कर सभी को आश्वस्त किया कि सब कुछ नियंत्रण में है। अपीलकर्ता का दावा है कि प्रबंधन ने उनके ईमानदार दृष्टिकोण की सराहना नहीं की और वास्तव में लापरवाही के कारण दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, उन्हें कार्रवाई के लिए चुना गया। उन्होंने केएपीपी के लिए आसन्न खतरे के प्रति अधिकारियों को सचेत करने में केवल अपना कर्तव्य निभाया था।

8. 'इनाम' के रूप में, प्रत्यर्थी अधिकारियों ने प्रमुख दंड के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार करते हुए, 5 जुलाई, 1994 के एक आदेश द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया। 4 अगस्त, 1994 को अपीलकर्ता को निम्नलिखित आरोप पत्र दिया गया: -

> “अनुच्छेद I: श्री मनोज मिश्रा ने, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में ट्रेड्समैन/बी के रूप में कार्य करते हुए, 18-6-1994 को संपादक, 'गुजरात समाचार' समाचार पत्र,

सूरत को लिखे अपने पत्र में, प्रेस के साथ अनधिकृत रूप से संवाद किया।

अनुच्छेद II: उक्त श्री मनोज मिश्रा ने, उपरोक्त परियोजना में ट्रेड्समैन/बी के रूप में कार्य करते हुए, उनके द्वारा संपादक, गुजरात समाचार को लिखे दिनांक 18-6-1994 के पत्र में कुछ बयान दिए या कुछ राय व्यक्त की, जो कि परियोजना प्रबंधन की आलोचना या इसके अधिकारियों की ईमानदारी पर आक्षेप लगाना।

अनुच्छेद III: उक्त श्री मनोज मिश्रा, उपरोक्त परियोजना में ट्रेड्समैन/बी के रूप में कार्य करते हुए, हालांकि उनका पत्र दिनांक 18-6-1994 था, उन्होंने गुजरात समाचार के संपादक को अनधिकृत रूप से प्रेस को काकरापार के संबंध में आधिकारिक जानकारी दी थी। परमाणु ऊर्जा परियोजना.

अनुच्छेद IV: उक्त श्री मनोज मिश्रा ने, उपरोक्त परियोजना में ट्रेड्समैन/बी के रूप में कार्य करते हुए, एक प्रेस संवाददाता के साथ संपर्क स्थापित किया, ताकि प्रेस को परियोजना के बारे में समाचार बनाने में मदद मिल सके,

जिसमें भड़काऊ और भ्रामक जानकारी शामिल थी, जो शर्मिंदगी और नुकसान पहुंचा रही थी। परियोजना और एनपीसीआईएल की प्रतिष्ठा।

अनुच्छेद V: उक्त श्री मनोज मिश्रा ने, उपरोक्त परियोजना में ट्रेड्समैन/बी के रूप में कार्य करते हुए, प्रेस संवाददाता के साथ संपर्क स्थापित किया और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी जो ट्रेड्समैन/बी के रूप में उनके कर्तव्य के दौरान उनके पास आई थी। परियोजना, प्रेस को परियोजना के बारे में एक समाचार कहानी बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे परियोजना के साथ-साथ राज्य के अधिकारियों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस प्रकार श्री मनोज मिश्रा ने गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है जो उन्होंने परियोजना में शामिल होने के समय ली थी।"

9. अपीलकर्ता 20 दिसंबर, 1995 को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, जब उसके बचाव सहायक (संक्षेप में 'डीए') ने निम्नलिखित बयान दिया: -

> "डीए. पूछताछ के संबंध में श्री मनोज मिश्रा दिनांक 18.12.95 को एमडी से मिले। उन्होंने 22.9.95 को एमडी से अपील की और इसका जिक्र करते हुए श्री मिश्रा ने एमडी से पूछा कि उनकी अपील पर उनका क्या निर्णय है। एमडी ने श्री मिश्रा को बताया कि अगर वह प्रभार स्वीकार कर लेते हैं तो नरम रुख अपनाया जायेगा. मैं भी आज उनसे मिला और उन्होंने मुझे भी ऐसा ही आश्वासन दिया। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, श्री मिश्रा अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार करते हैं और तदनुसार कार्यवाही बंद करने का अनुरोध करते हैं। अब हम आईओ से भी मामले पर नरम रुख अपनाने का अनुरोध करते हैं।"

10. हालाँकि, जाँच अधिकारी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ सशर्त प्रवेश स्वीकार करने से इनकार कर दिया:-

> "आईओ पूछताछ में ऐसी स्वीकारोक्ति वैध नहीं है। आपकी एमडी से मुलाकात एक अनावश्यक मामला है जिससे मेरा जांच अधिकारी को कोई सरोकार नहीं है। इसके अलावा, मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि आप तथ्यों के अलावा अन्य कारणों से आरोपों को स्वीकार करें। इसलिए, मैं

आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आप स्वयं आरोपों को स्वीकार करते हैं या नहीं।"

11. जांच अधिकारी के उपरोक्त अनुरोध के जवाब में, अपीलकर्ता, यानी सीओ ने इस प्रकार कहा:-

"सीओ मैं आरोप स्वीकार करता हूं। मैं जांच बंद करने का अनुरोध करता हूं।"

12. उपरोक्त स्वीकारोक्ति के मद्देनजर, जांच अधिकारी ने जांच कार्यवाही बंद कर दी। अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध माने गये। दिनांक 30 मार्च, 1996 के आदेश द्वारा उपरोक्त जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को 30 मार्च, 1996 की दोपहर से केएपीपी की सेवा से हटाने का आदेश दिया। अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि उपरोक्त आदेश के खिलाफ स्टेशन में एक अपील है। आदेश जारी होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर निदेशक, केएपीपी। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी नंबर 3 के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जिसे भी खारिज कर दिया गया।

13. अपीलकर्ता ने 1997 के एक विशेष सिविल आवेदन संख्या 2115 के माध्यम से उपरोक्त आदेश को चुनौती दी। उपरोक्त रिट याचिका को

विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त फैसले के खिलाफ एलपीए नंबर 1041/2007 को प्राथमिकता दी, जिसे 14 जुलाई, 2009 को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था। इन सभी आदेशों को वर्तमान अपील में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

14. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

15. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने कहा कि अपीलकर्ता ने इस देश के एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में अधिकारियों की ओर से गंभीर खामियों को उजागर करके केवल अपना कर्तव्य निभाया है जिसके परिणामस्वरूप एक भयावह दुर्घटना हो सकती है। विद्वान वकील ने बताया कि केएपीपी में हुई दुर्घटना की गंभीरता इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसका उल्लेख परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारतीय परमाणु स्थापना की सुरक्षा पर सरकार को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। विद्वान वकील ने आगे बताया कि केएपीपी को बिजली आपूर्ति केवल 1510 बजे बहाल की जा सकी। 16 जून 1994 को प्लांट का कुछ हिस्सा 17 जून 1994 को सुबह 10.25 बजे ही दोबारा शुरू हो सका। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि घटना के दौरान साइट आपातकाल सुबह 11.00 बजे घोषित किया गया था और 16 जून, 1994 को शाम 5.00 बजे समाप्त कर दिया गया था। ऑडिट रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित

करती है कि जिन तीन घटनाओं की समीक्षा की गई, उनसे उत्पन्न मूल्यवान फीडबैक ने इस घटना का संकेत दिया। केएपीएस ने देश में परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के डिजाइन को मजबूत करने का नेतृत्व किया। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, अपीलकर्ता को दंडित करने के बजाय, इस देश के एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। विद्वान वकील ने आगे बताया कि एक बार आंतरिक आपातकाल घोषित हो जाने के बाद, प्रत्यर्थी नंबर 2 से 4 का दायित्व था कि वे कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, सूरत, व्यारा, मांडवी, ओलपाड के एसडीएम, डीएसपी (ग्रामीण), सूरत को आपातकाल के बारे में सचेत करें। हालाँकि, KAPP प्राधिकरण ने 16 जून, 1994 को जिला प्रशासन के अधिकारियों को सचेत नहीं किया। वास्तव में, 22 जून, 1994 को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में नई कहानियाँ प्रकाशित होने के बाद जिला प्राधिकरण ने 23 जून, 1994 को ही साइट का दौरा किया। श्री प्रशांत भूषण ने 2 जुलाई, 1994 के पत्र का संदर्भ दिया है, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को सूचित किया है कि:

> "प्रेस में अत्यधिक भड़काऊ समाचारों के प्रकट होने के परिणामस्वरूप, जिला प्रशासन के अधिकारियों को कहानी की सत्यता का पता लगाने और आशंकाओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए

23.6.1994 को शिकायत स्थल पर जाना पड़ा। समाचार कहानी के कारण चारों ओर हंगामा हुआ। परियोजना अधिकारियों को भी प्रेस को स्पष्टीकरण सूचना जारी करने के लिए उचित तत्काल कार्रवाई करने के लिए 23.6.1994 को जिला मुख्यालय जाना पड़ा। इन सब से बचा जा सकता था यदि श्री मनोज मिश्रा और उनके साथी जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करते और प्रेस के साथ बातचीत करने और विकृत जानकारी प्रसारित करने से बचते।

चूंकि श्री मनोज मिश्रा और उनके सहयोगियों की ओर से की गई कार्रवाई ने प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के अलावा विभिन्न अधिकारियों के लिए गंभीर कठिनाइयां पैदा की हैं और अपने स्वयं के कुछ कर्मचारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसलिए जिला प्रशासन अधिकारियों ने परियोजना प्रबंधन से पूरे प्रकरण की जांच करने और दोषियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करने को कहा है।"

16. श्री प्रशांत भूषण ने कथन किया कि यदि अपीलकर्ता का उद्देश्य प्रचार प्राप्त करना था, तो वह 16 जून, 1994 या 17 जून, 1994 को प्रेस के

पास जा सकते थे। अपीलकर्ता ने पत्रकारों से केवल तभी बात की जब वे थे स्थिति को कवर करने के लिए संयंत्र स्थल पर। उन्होंने केएकेएस के महासचिव के तौर पर प्रेस से बात की थी. विद्वान वकील ने बताया कि अपीलकर्ता ने 18 जून, 1994 को गुजरात समाचार के संपादक को केवल तभी पत्र लिखा था, जब उसने देखा कि संबंधित अधिकारी लापरवाही से काम कर रहे थे। श्री भूषण ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने के लिए गुमराह किया गया है क्योंकि उसे प्रत्यर्थी नंबर 4 द्वारा मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया था कि यदि वह सभी आरोपों को स्वीकार करता है तो उसके साथ नरमी से निपटा जाएगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने परमाणु सुविधा के सर्वोत्तम हित में और फुकुशिमा दुर्घटना जैसे विनाशकारी परिणाम वाली भयावह दुर्घटना को रोकने के लिए काम किया था, अपीलकर्ता को किसी भी कदाचार का दोषी नहीं कहा जा सकता है। श्री भूषण ने आगे कहा कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई जानकारी, किसी भी तरह से, किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही या दंड को आमंत्रित करने के लिए गोपनीय जानकारी नहीं थी। अपीलकर्ता, वास्तव में, एक "व्हिसल ब्लोअर" की स्थिति में था और उसे न्यायालय द्वारा पूर्ण सुरक्षा दी जानी थी। विद्वान वकील ने बताया कि परमाणु रिएक्टर बंद होने के बाद भी रेडियो गतिविधि लंबे समय तक जारी रहेगी, इसलिए, ईंधन की छड़ों को बहुत लंबे समय

तक और कभी-कभी वर्षों तक भी ठंडा रखना पड़ता है। 15 जून 1994 की रात को हुई यह घटना बेहद गंभीर थी. बिजली गुल होने का विनाशकारी प्रभाव हो सकता था। इसलिए, नागरिक अधिकारियों को तुरंत सतर्क होना पड़ा, क्योंकि पूरे क्षेत्र की आबादी को खाली करना होगा। समय पर निवारक उपाय करने के बजाय, परमाणु केंद्र ने केवल घटना को छिपाए रखने की कोशिश की। केवल इसलिए कि बाढ़ से होने वाली क्षति को अंततः नियंत्रित कर लिया गया, यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है कि इससे बड़ी तबाही नहीं होगी। अपीलकर्ता ने केवल सिविल अधिकारियों को सचेत किया था, जो नियमों के तहत प्रतिवादियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक था। श्री भूषण ने दोहराया कि अधिकारियों द्वारा स्वयं दिए गए घटना के विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अंततः स्थल पर बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की गई थी। विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया गया और उनकी कार्रवाई के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। विद्वान वकील ने केएपीएस खंड । भाग ॥, पृष्ठ 3 के लिए आपातकालीन तैयारी पर मैनुअल के उद्धरण और साइट आपातकाल के लिए कार्य योजना को भी दोहराया। उन्होंने विशेष रूप से हमारे ध्यान में लाया कि आपातकालीन सिग्नल सुनने पर और/या टेलीफोन (या किसी अन्य माध्यम) के माध्यम से इसकी जानकारी मिलने पर, निदेशक को तुरंत मुख्य नियंत्रण कक्ष में जाना होगा। उन्हें सूरत के

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, व्यारा, मांडवी, ओलपाड के एसडीएम, डीएसपी (ग्रामीण), सूरत को सचेत करना आवश्यक है। उपर्युक्त के खंड 5 के अंतर्गत मैनुअल से उद्धरण। अधिकारियों को सामान्य संदूषण और विकिरण जांच के लिए विधानसभा क्षेत्रों में एक सहायक स्वास्थ्य भौतिक विज्ञानी को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के बाद घायल व्यक्ति/व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। यदि आवश्यक हो, तो साइट कर्मियों की निकासी की व्यवस्था की जानी थी। चूँकि इनमें से कुछ भी नहीं किया जा रहा था, अपीलकर्ता ने "व्हिसल ब्लोअर" के रूप में काम किया और प्रेस को सचेत किया।

17. श्री भूषण केएकेएस के अध्यक्ष के रूप में अपीलकर्ता को वरिष्ठ प्रबंधक (पी एंड आईआर) के 2 जुलाई, 1994 के पत्र का संदर्भ देते हैं जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि "गुजरात समाचार में छपी कहानी ने लोगों के बीच घबराहट पैदा कर दी।" विशेष रूप से परियोजना के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग और सामान्य तौर पर गुजरात राज्य तथा राज्य प्रशासन, जिससे गलत सूचना फैल गई और परियोजना की बदनामी हुई, जिससे परियोजना की सुरक्षा और परियोजना प्राधिकरणों की अखंडता के बारे में संदेह पैदा हो गया। "।

18. इसलिए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं करके गंभीर त्रुटि की है कि सजा कदाचार के अनुपात से अधिक थी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय किसी तकनीकी से बाध्य नहीं है और उसे पर्याप्त न्याय करने की आवश्यकता होती है जहां घोर अन्याय सकारात्मक कार्रवाई की मांग करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में यदि निष्कासन की सजा को संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धि रोकने की सजा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वह गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड और अन्य पर निर्भर है।बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा और अन्य।[1], जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

> "हालांकि अनुच्छेद 226 के तहत उपाय असाधारण है और एंग्लो-सैक्सन विंटेज है, यह अंग्रेजी प्रक्रियाओं की कार्बन कॉपी नहीं है। अनुच्छेद 226 एक सौम्य सर्जरी है लेकिन
>
> लैंसेट वहां काम करता है जहां अन्याय होता है। जबकि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता जैसे पारंपरिक प्रतिबंध अदालत को रोकते हैं, और न्यायिक शक्ति को आम तौर पर वहां जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जहां अन्य दो शाखाएं

चलने से डरती हैं, न्यायिक साहस भयभीत नहीं होता है जहां घोर अन्याय भी सकारात्मक कार्रवाई की मांग करता है। अनुच्छेद 226 के व्यापक शब्द उनकी शिकायतों में कम संख्या की सेवा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं यदि विषय अदालत के प्रांत से संबंधित है और उपाय न्यायिक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है।"

19. उपरोक्त टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, उनका मानना है कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है। सिंगे न्यायाधीश, इस सिद्धांत पर ध्यान देने के बाद भी कि न्यायालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है, यदि यह अवैध लगता है या प्रक्रियात्मक अनौचित्य से ग्रस्त है या न्यायालय की न्यायिक चेतना के लिए चौंकाने वाला है, तो गलती से इसे लागू करने में विफल रहा। अपीलकर्ता के मामले में.

20. अपीलकर्ता पर लगाया गया दंड अतार्किकता, विकृति और आश्चर्यजनक रूप से असंगत होने के सभी दोषों से ग्रस्त है और इसे अलग रखा जाना चाहिए और कम सजा से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। प्रस्तुतियाँ के समर्थन में, वह रंजीत ठाकुर बनाम पर भरोसा करते हैं।

भारत संघ एवं अन्य।[2], जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:-

"25. आम तौर पर न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय के विरुद्ध निर्देशित नहीं होती, बल्कि "निर्णय लेने की प्रक्रिया" के विरुद्ध निर्देशित होती है। सज़ा के चयन और मात्रा का प्रश्न कोर्ट-मार्शल के अधिकार क्षेत्र और विवेक के अंतर्गत है। लेकिन सज़ा अपराध और अपराधी के अनुरूप होनी चाहिए। यह प्रतिशोधात्मक या अनावश्यक रूप से कठोर नहीं होना चाहिए। यह अपराध के प्रति इतना असंगत नहीं होना चाहिए कि अंतरात्मा को झकझोर दे और अपने आप में पक्षपात का निर्णायक सबूत बन जाए। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के हिस्से के रूप में आनुपातिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ऐसे पहलू पर भी, जो अन्यथा, कोर्ट-मार्शल के विशेष प्रांत के भीतर है, यदि सजा के संबंध में भी अदालत का निर्णय एक अपमानजनक अवज्ञा है तर्क का, तो वाक्य सुधार से अछूता नहीं रहेगा। तर्कहीनता और विकृति न्यायिक समीक्षा के मान्यता प्राप्त आधार हैं। सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री9 में लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा:

"मुझे लगता है कि न्यायिक समीक्षा आज एक ऐसे चरण में विकसित हो गई है, जहां विकास के चरणों के किसी भी विश्लेषण को दोहराए बिना, कोई भी आसानी से तीन प्रमुखों के तहत वर्गीकृत कर सकता है, जिन आधारों पर प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रित होती है। पहले आधार को मैं 'अवैधता', दूसरे को 'तर्कहीनता' और तीसरे को 'प्रक्रियात्मक अनौचित्य' कहूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मामले-दर- मामले के आधार पर आगे का विकास समय के साथ और आधार नहीं जोड़ सकता है। मेरे मन में विशेष रूप से भविष्य में 'आनुपातिकता' के सिद्धांत को संभावित रूप से अपनाने की बात है, जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के हमारे कई साथी सदस्यों के प्रशासनिक कानून में मान्यता प्राप्त है।"

21. एक ही प्रस्ताव पर, विद्वान वकील ने कई निर्णयों पर भरोसा किया है, लेकिन उनका संदर्भ देना आवश्यक नहीं है क्योंकि उपरोक्त मामलों में निर्धारित कानून का अनुपात केवल दोहराया गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 21 अप्रैल, 2004 को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने परिवर्तन और अन्य में इस न्यायालय के आदेश के संदर्भ में "व्हिसल ब्लोअर्स" की सुरक्षा के लिए एक अधिसूचना जारी की

थी। बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2004 की रिट याचिका (सी) संख्या 93, 2003 की रिट याचिका (सी) संख्या 539 के साथ श्री सत्येन्द्र दुबे की हत्या की रिकॉर्डिंग। उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। आरके जैन[3] ने अपने निवेदन के समर्थन में कहा कि अपीलकर्ता ने "व्हिसल ब्लोअर" के रूप में काम किया था, उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए था।

22. श्री पारेख ने अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा बताई गई घटनाओं के संस्करण पर गंभीरता से विवाद किया है। उनका कहना है कि 16 जून, 1994 को, अतिप्रवाह के परिणामस्वरूप, बाढ़ का पानी संयंत्रों के कुछ हिस्सों में घुस गया और इसलिए, एहतियाती कार्रवाई की जानी थी। इसलिए, जब हर कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बचाने के लिए स्थिति से निपटने में व्यस्त था, तब अनुवर्ती अभ्यास परिश्रमपूर्वक किए जा रहे थे, अपीलकर्ता ने आधिकारिक टेलीफोन का उपयोग करके मीडिया के निम्नलिखित सदस्यों से संपर्क किया: -

i) 623375-संपादक, गुजरात समाचार, सूरत

ii) 20760- श्री विलासभाई सोनी, प्रेस रिपोर्टर, संदेश, व्यार

iii) 30225-हसमुखलाल एंड कंपनी, सरदार चौक, बारडोली।

23. 18 जून, 1994 को, लगभग 11.30 बजे, अपीलकर्ता ने सीआईएसएफ के पास सेक्शन को फोन किया और श्री ए. श्रीकृष्ण, सीआईएसएफ कांस्टेबल को बताया कि एक व्यक्ति उससे पूछने के लिए पास सेक्शन में आएगा। कांस्टेबल से कहा गया कि वह उस व्यक्ति से अपीलकर्ता की प्रतीक्षा करने को कहे। प्रेस रिपोर्टर के आने के बाद, अपीलकर्ता ने उनसे उनके आधिकारिक क्वार्टर में मुलाकात की। इसके बाद, अपीलकर्ता ने गुजरात में सबसे अधिक प्रसार संख्या वाले दैनिक गुजरात समाचार पत्र को पत्र लिखा। उक्त बात पर भरोसा करते हुए अखबार ने खबर प्रकाशित की. इसके तुरंत बाद 22 जून 1994 को गुजरात समाचार में एक और समाचार छपा जिसका शीर्षक था कि "15 जून को आधा गुजरात फट गया होता"। इस समाचार में कहा गया था कि "साथ ही किसी दुर्घटना से न केवल सूरत जिले, बल्कि पूरे गुजरात को नुकसान पहुंचने और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से ध्वस्त होने की संभावना से बचा लिया गया है।" श्री पारेख के अनुसार, उपरोक्त कहानी में "संगठन में चल रहे ज़बरदस्त भ्रष्टाचार" के झूठे और मानहानिकारक आरोप शामिल थे। इसने परियोजना के बारे में गलत और विकृत तथा भड़काऊ जानकारी दी, जिससे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा के बारे में गंभीर संदेह पैदा हो गया। उपरोक्त समाचार गुजरात की जनता में अत्यधिक दहशत पैदा करने में सक्षम था। सुरक्षा स्थितियों से संतुष्ट होने के बाद, केएपीएस के साइट आपातकालीन

योजना के निदेशक के रूप में जिला कलेक्टर ने इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति दी। इसी प्रकार, स्टेशन निदेशक ने भी अपीलकर्ता द्वारा अपने नाम और हस्ताक्षर से जारी समाचार से उत्पन्न घबराहट की स्थिति को दूर करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। ये स्पष्टीकरण 23 जून, 1994 को गुजरात समाचार में प्रकाशित हुए थे। 5 जुलाई, 1994 को, प्रत्यर्थी नंबर 2 ने उपरोक्त मीडिया रिपोर्टों के पीछे अपीलकर्ता की भूमिका की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को बड़े दंड के लिए उसके खिलाफ शुरू की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार करते हुए निलंबित कर दिया। आरोपों के समर्थन में कदाचार के आरोप का बयान अपीलकर्ता को 4 अगस्त, 1994 को दिया गया था। 26 दिसंबर, 1994 को एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच में प्राथमिक सुनवाई में, अपीलकर्ता ने सभी आरोपों से इनकार किया। रक्षा सहायक के रूप में श्री पीबी शर्मा की उनकी पसंद को स्वीकार कर लिया गया। उनसे सभी दस्तावेजों का निरीक्षण कराया गया, उनसे गवाहों की सूची भी जमा करने को कहा गया. अपीलकर्ता ने कहा था कि गवाहों की सूची उसके बचाव सहायक से परामर्श करने के बाद प्रस्तुत की जाएगी। 9 अक्टूबर, 1995 को जांच की सुनवाई इस आधार पर स्थगित कर दी गई कि अपीलकर्ता ने एनपीसीआईएल को एक अपील प्रस्तुत की थी। 20 दिसंबर, 1995 को, अपीलकर्ता ने अपने

खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और तदनुसार आरोपों की स्वीकृति पर जांच बंद कर दी गई।

24. श्री पारेख ने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसे इस आधार पर आरोपों से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि प्रतिवादियों द्वारा उसे उदारता का कोई आश्वासन दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता हर चरण में अनुपयुक्त रहा है। यहां तक कि इस कोर्ट ने सजा के सवाल पर सिर्फ नोटिस जारी किया था. वह बताते हैं कि अपीलकर्ता यह कहने में सही है कि वह कपड़ा मिल या चीनी मिल का कर्मचारी नहीं है, वह अत्यधिक संवेदनशील परमाणु केंद्र का कर्मचारी था। घटना के समय उनसे उच्चतम स्तर की गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा की गई थी। अपीलकर्ता, बाढ़ की स्थिति के नियंत्रण में सहायता करने के बजाय, प्रेस को दुष्प्रचार देने में व्यस्त था। उन्होंने कहा कि परमाणु केंद्र पर लागू नियमों और विनियमों के तहत, निर्दिष्ट अधिकारी के अलावा किसी अन्य कर्मचारी द्वारा प्रेस से संपर्क नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमाणु ऊर्जा सुविधा में काम करने वाले कर्मचारी एक विशेष श्रेणी के कर्मचारी हैं। अत्यधिक संवेदनशील जानकारी के रिसाव को रोकने के लिए उन्हें गोपनीयता के संबंध में बहुत उच्च मानक बनाए रखने की आवश्यकता होती है। श्री पारेख ने अपीलकर्ता के इस दावे का जोरदार

खंडन किया कि वह एक "व्हिसल ब्लोअर" है। जिस समय पानी परमाणु संयंत्र में प्रवेश कर रहा था, उस समय अपीलकर्ता ने मीडिया को तीन टेलीफोन कॉल करके जानकारी दी, जिसे देने की उसे अनुमति नहीं थी। अपीलकर्ता ने 18 जून, 1994 को ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को एक समाचार संवाददाता को बाहर रखने के लिए भी सूचित किया था, जब आपातकाल अपने चरम पर था। श्री पारेख ने आगे बताया कि अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए आरोपों के मात्र अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि सजा न केवल उचित है बल्कि वास्तव में काफी उदार है। वास्तव में प्रतिवादियों के पास अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने का विकल्प था लेकिन उसके खिलाफ केवल विभागीय कार्यवाही की गई है। श्री पारेख ने यह भी प्रस्तुत किया कि श्री भूषण द्वारा की गई अधिकांश प्रस्तुतियाँ और प्रस्तुतियाँ के समर्थन में जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, वे कभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार अपीलकर्ता किसी भी प्रकार की नरमी का पात्र नहीं है और अपील खारिज किये जाने योग्य है।

25. हमने विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर बहुत उत्सुकता से विचार किया है।

26. हमने श्री भूषण द्वारा की गई दलीलों को विस्तार से नोट किया है, हालांकि कड़ाई से बोलते हुए, जांच अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा

की गई स्पष्ट स्वीकृति के मद्देनजर यह आवश्यक नहीं था। आरोपों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के बाद, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष केवल सजा में कमी की गुहार लगाई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से देखा है कि अपीलकर्ता के वकील ने केवल यह प्रस्तुत किया है कि सजा अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए कदाचार की गंभीरता के अनुपात में नहीं है। अपराध के निष्कर्षों में चुनौती को शामिल करने के लिए अपील के आधारों में संशोधन के लिए एलपीए में डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना खारिज कर दी गई।

27. हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। हम इस मुद्दे की जांच करने के इच्छुक नहीं हैं कि अपीलकर्ता के कार्य नियमों के तहत कदाचार नहीं होंगे। अपीलकर्ता द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के मद्देनजर, किसी भी पक्ष द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। एक बार जब जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता द्वारा की गई सशर्त स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उसके पास आरोपों से इनकार करने का विकल्प खुला था। लेकिन उन्होंने 26 दिसंबर, 1994 को हुई प्रारंभिक सुनवाई में दर्ज किए गए अपने पहले के इनकार को दोहराने के बजाय, एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति करने का विकल्प चुना। अपीलकर्ता को अब जांच अधिकारी के समक्ष की

गई स्वीकारोक्ति से मुकरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जांच दोबारा शुरू करने की याचिका अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने खारिज कर दी है। इसके बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इस पर बहस भी नहीं की गई। विद्वान वकील ने दलील को सजा की मात्रा तक ही सीमित रखा था। एलपीए में, डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे को फिर से खोलने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में, हम इस स्तर पर पूरे मुद्दे को फिर से खोलने के लिए अनुच्छेद 136 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसी शक्ति इस न्यायालय को न्याय के गंभीर गर्भपात को रोकने में सक्षम बनाने के लिए आरक्षित है। आमतौर पर इसका प्रयोग तब नहीं किया जाता जब उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा दृष्टिकोण अपनाया हो जो उचित रूप से संभव हो। अपीलकर्ता एकल न्यायाधीश या उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों में कोई विकृति प्रदर्शित करने में विफल रहा है।

28. संपूर्ण तथ्य स्थिति की जांच करने के बाद, हम श्री भूषण की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ता "व्हिसल ब्लोअर" के रूप में कार्य कर रहा था। इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा है: -

> “इस समय, व्हिसलब्लोअर की घटना की बढ़ती स्वीकार्यता पर ध्यान देना उचित होगा। व्हिसलब्लोअर वह व्यक्ति होता

है जो किसी संगठन या लोगों के निकाय में होने वाले गलत कार्यों के बारे में चिंता व्यक्त करता है। आमतौर पर यह व्यक्ति उसी संगठन से होगा. प्रकट कदाचार को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है; उदाहरण के लिए, किसी कानून, नियम, विनियमन का उल्लंघन और/या सार्वजनिक हित के लिए सीधा खतरा, जैसे धोखाधड़ी, स्वास्थ्य/सुरक्षा उल्लंघन और भ्रष्टाचार। व्हिसिलब्लोअर अपने आरोप आंतरिक रूप से (उदाहरण के लिए, आरोपी संगठन के भीतर अन्य लोगों पर) या बाहरी रूप से (नियामकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, मीडिया या मुद्दों से संबंधित समूहों पर) लगा सकते हैं।"

29. उपरोक्त टिप्पणी करने से पहले, इस न्यायालय ने लंबी अवधि में हुई विभिन्न घटनाओं की विस्तार से जांच की, जिसमें प्रत्यर्थी, लॉ जर्नल, एक्साइज लॉ टाइम्स के संपादक ने भाग लिया था। अपीलकर्ता संघ द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ इस आधार पर एक अवमानना याचिका दायर की गई थी कि उसने जर्नल के 1 जून, 2009 के अंक में एक संपादकीय लिखा था, जो अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत आपराधिक अवमानना है। 1971. संपादकीय में, प्रत्यर्थी ने प्रशासन को शुद्ध करने के लिए CESTAT के नए अध्यक्ष द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना

की। हालाँकि, साथ ही, उन्होंने ट्रिब्यूनल के कुछ सदस्यों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में अनियमितताओं को भी उजागर किया। उन्होंने बताया था कि एक विशेष सदस्य, श्री टी.के. जयारमन को उनकी पोस्टिंग के एक वर्ष से भी कम समय में एक अन्य सदस्य को बैंगलोर से दिल्ली स्थानांतरित करके बैंगलोर में समायोजित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने श्री टी.के.जयरामन की पीठ द्वारा पारित कुछ आदेशों की भी आलोचना की थी, जिन पर कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालय ने प्रतिकूल टिप्पणी की थी। इसके बावजूद, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि, श्री टीके जयरमण को दिखाई गई अनियमितताओं और ज़बरदस्त पक्षपात को उजागर करके, श्री आरके जैन CESTAT की कार्यप्रणाली को बदनाम करने और जनता की नज़र में इसके सम्मान को कम करने की कोशिश कर रहे थे। यह बताया गया कि जिस लेख में उपरोक्त बयान दिए गए हैं, वह इस न्यायालय में 1997 की अवमानना याचिका (सीआरएल) संख्या 15 में दायर उपक्रम का उल्लंघन था। इन कार्यवाहियों में, प्रत्यर्थी ने एक वचन दिया था 25 अगस्त, 1998 को अपने वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई सलाह का पालन करने के लिए कि भविष्य में जब भी सीईजीएटी के कामकाज के संबंध में कोई गंभीर शिकायत हो, तो उचित कदम यह होगा कि पहले उन मामलों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में लाया जाए। और/या वित्त मंत्रालय और कोई अन्य कार्रवाई करने से पहले उचित समय के लिए प्रतिक्रिया या

सुधारात्मक कार्रवाई की प्रतीक्षा करें। उपरोक्त अवमानना मामले के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी ने CESTAT में अनियमितताओं, खराबी और भ्रष्टाचार के विशिष्ट मामलों को उजागर करते हुए वित्त मंत्री और भारत सरकार के अन्य उच्च अधिकारियों को कई विस्तृत पत्र लिखे थे। अवमानना का नोटिस खारिज होने के बाद, प्रत्यर्थी ने इसी विषय पर वित्त मंत्री को दो और पत्र लिखे और यह भी बताया कि कैसे श्री टी.के. जयारमन, सदस्य सीईएसटीएटी की नियुक्ति और पोस्टिंग अनियमित थी। उन्होंने राजस्व सचिव को भी ऐसे ही पत्र लिखे; अध्यक्ष, CESTAT; रजिस्ट्रार, CESTAT और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। चूँकि उपरोक्त पत्रों पर पाँचों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, प्रत्यर्थी ने संपादकीय लिखा जिसमें उसने टिप्पणियाँ कीं जिस कारण अपीलार्थी को हस्तगत अवमानना याचिका दायर करनी पडी।

30. इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी के आचरण और साख पर ध्यान दिया। यह देखा गया है कि प्रत्यर्थी पत्रकारिता के क्षेत्र में नौसिखिया नहीं है। दशकों से, वह निडर होकर सीईजीएटी और उसके उत्तराधिकारी सीईएसटीएटी की खराबी को उजागर करने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल कर रहे थे। 26 दिसंबर, 1991 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे अपने पत्र में उन्होंने शिकायत की कि सीईजीएटी पिछले छह महीने से अधिक समय से अध्यक्ष के बिना है, जिससे

ट्रिब्यूनल के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों के गहन विश्लेषण के बाद, इस न्यायालय ने सीईजीएटी और अनुच्छेद 323ए और 323बी के तहत गठित अन्य न्यायाधिकरणों के कामकाज में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए। [आरके जैन बनाम भारत संघ, (1993) 4 एससीसी 119]। यह बताया गया कि सीईजीएटी के कामकाज के संबंध में श्री आर.के. जैन दवारा न्यायाधिकरण का कार्य पर भी आक्षेप लगाये गये हैं।

31. पहले मामले में उपरोक्त टिप्पणियों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने अप्रत्यक्ष कर प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (सुप्रा) के मामले में बताया कि प्रत्यर्थी पहले की अवमानना याचिका में दायर उपक्रम के प्रति बहुत सचेत था और यही कारण है कि पहले संपादकीय लिखते हुए, उन्होंने CESTAT के कामकाज में अनियमितताओं को उनके ध्यान में लाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को कई पत्र भेजे। न्यायालय ने कहा कि "उन पत्रों को लिखने का एकमात्र उद्देश्य संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाना था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस समस्या को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। यह न तो अपीलकर्ता का दावा किया गया मामला है और न ही इस न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रखी गई है कि भारत सरकार के वित्त मंत्री या राजस्व सचिव ने प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में कोई

उपचारात्मक कार्रवाई की थी। इसलिए, प्रत्यर्थी को इस न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करने का दोषी ठहराना संभव नहीं है।

32. इस न्यायालय ने संपूर्ण तथ्य स्थिति पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने पर पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा लिखे गए संपादकीय का उद्देश्य एक संस्था के रूप में CESTAT को नीचा दिखाना या उसकी कार्यप्रणाली को बदनाम करना नहीं था। बल्कि, संपादकीय का उद्देश्य CESTAT के सदस्यों की नियुक्ति, पोस्टिंग और स्थानांतरण में अनियमितताओं और अर्ध न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग के उदाहरणों को उजागर करना था। आगे यह देखा गया कि संपादकीय में श्री टी.के.जयरमण की विशेष पीठ द्वारा पारित आदेशों की असंतोषजनक प्रकृति पर प्रकाश डाला गया। उक्त आदेशों को कर्नाटक और केरल के उच्च न्यायालयों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा भी रद्द कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने कहा:-

> "38. अपीलकर्ता का मामला यह नहीं है कि CESTAT के सदस्यों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में संपादकीय में बताए गए तथ्य गलत हैं या प्रत्यर्थी ने किसी परोक्ष उद्देश्य से इसे उजागर किया है या कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश गलत हैं। संपादकीय में जो संदर्भ दिया गया है, उसे इस न्यायालय ने उलट दिया है। इसलिए, इस निष्कर्ष को दर्ज करना संभव

नहीं है कि प्रश्न में संपादकीय लिखकर, प्रत्यर्थी ने CESTAT के कामकाज को बदनाम करने की कोशिश की है या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है।"

41. आंतरिक मुखबिरों के संबंध में सबसे दिलचस्प प्रश्नों में से एक यह है कि क्यों और किन परिस्थितियों में लोग अवैध और अन्यथा अस्वीकार्य व्यवहार को रोकने के लिए मौके पर ही कार्रवाई करेंगे या इसकी रिपोर्ट करेंगे। यह मानने का कुछ कारण है कि किसी संगठन के भीतर अस्वीकार्य व्यवहार के संबंध में लोगों द्वारा कार्रवाई करने की अधिक संभावना है, यदि शिकायत प्रणालियाँ हैं जो न केवल योजना और नियंत्रण संगठन द्वारा निर्धारित विकल्प प्रदान करती हैं, बल्कि व्यक्तियों के लिए विकल्पों का विकल्प भी प्रदान करती हैं। इसमें एक ऐसा विकल्प शामिल है जो लगभग पूर्ण गोपनीयता प्रदान करता है। हालाँकि, बाहरी मुखबिर बाहरी व्यक्तियों या संस्थाओं पर कदाचार की रिपोर्ट करते हैं। इन मामलों में, सूचना की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर, व्हिसलब्लोअर वकीलों, मीडिया, कानून प्रवर्तन या निगरानी एजेंसियों, या अन्य स्थानीय, राज्य या संघीय एजेंसियों को कदाचार की रिपोर्ट कर सकते हैं।

> 42. हमारे विचार में, प्रत्यर्थी जैसे व्यक्ति को सिस्टम के लिए व्हिसलब्लोअर के रूप में उचित रूप से वर्णित किया जा सकता है, जिसने राज्य के राजस्व से जुड़े मामलों से निपटने के लिए स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्थान की खराबी को उजागर करने की कोशिश की है और ऐसे व्यक्ति को चुप कराने का कोई कारण नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 129 या 215 या अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके एक व्यक्ति।"

33. हमारी राय में, उपरोक्त टिप्पणियाँ अपीलकर्ता के लिए कोई लाभकारी नहीं हैं। यह रिकॉर्ड की बात है कि अपीलकर्ता केवल 12 वीं कक्षा तक शिक्षित है। वह न तो कोई इंजीनियर है और न ही परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कार्यप्रणाली का विशेषज्ञ है। एक अंदरूनी सूत्र होने के अलावा, अपीलकर्ता "व्हिसल ब्लोअर" का दर्जा दिए जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करता था। किसी व्यक्ति को "व्हिसल ब्लोअर" के रूप में स्वीकार किए जाने की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक यह है कि गतिविधि का उसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी सार्वजनिक संगठन या प्राधिकरण की अवैध गतिविधियों को उजागर करते हुए, सार्वजनिक हित में गतिविधि की जानी चाहिए। अपीलकर्ता का आचरण, हमारी राय में, उच्च नैतिक और नैतिक

मानक के अंतर्गत नहीं आता है जो एक वास्तविक "व्हिसल ब्लोअर" के लिए आवश्यक होगा।

34. हमारी राय में, अपीलकर्ता ने बिना किसी औचित्य के निगरानीकर्ता की भूमिका निभाई। हम यह नहीं पाते हैं कि उत्तरदाताओं की ओर से इस आशय की प्रस्तुतियाँ कि अपीलकर्ता केवल प्रचार चाह रहा था, बिना किसी तथ्य के हैं। अखबार की रिपोर्टों के साथ-साथ अन्य प्रचारों ने निस्संदेह स्थानीय आबादी के साथ-साथ पूरे गुजरात राज्य में काफी दहशत पैदा कर दी। प्रत्येक मुखबिर को स्वचालित रूप से एक प्रामाणिक "व्हिसल ब्लोअर" नहीं कहा जा सकता है। एक "व्हिसल ब्लोअर" वह व्यक्ति होगा जिसमें एक योद्धा के गुण हों। उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और प्रेरणा में संदेह के लिए बहुत कम या कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि ऐसा व्यक्ति एक ही संगठन से है और उसे कुछ ऐसी जानकारी है जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। किसी व्यक्ति को "व्हिसल ब्लोअर" कहलाने की कार्रवाई की प्राथमिक प्रेरणा किसी संगठन को शुद्ध करना होना चाहिए। यह किसी गुप्त या स्वार्थी उद्देश्य के लिए की गई कार्रवाई का आकस्मिक या उपोत्पाद नहीं होना चाहिए।

35. हमारी सुविचारित राय है कि यहां अपीलकर्ता की कार्रवाई केवल संगठन में कमियों को उजागर करने के लिए नहीं थी। अपीलकर्ता ने संगठन के भीतर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए

निंदनीय टिप्पणी की थी।इस तरह के आरोपों से पूरे प्रोजेक्ट की अखंडता पर संदेह की छाया पड़ने के अलावा पूरे संगठन पर स्पष्ट रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि अत्यधिक संवेदनशील परमाणु संगठन के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और उन्हें गोपनीयता समझौता करना पड़ता है। हमारी राय में, अपीलकर्ता गोपनीयता और विवेक के मानक को बनाए रखने में विफल रहा, जिसे बनाए रखा जाना आवश्यक था। इस मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता अप्रत्यक्ष कर प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का कोई लाभ नहीं उठा सकता है। यह अब हमें गुजरात स्टील ट्यूब्स केस (सुप्रा) के मामले में फैसले पर अपीलकर्ता द्वारा रखी गई निर्भरता की ओर ले जाता है। हमारी राय में, उपरोक्त निर्णय में अनुपात की अपीलकर्ता के मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि यह 'घोर अन्याय' का मामला है।

36. हमारी राय में, अपीलकर्ता को दी गई सजा 'अपराध के प्रति इतनी असंगत नहीं है कि इस न्यायालय की अंतरात्मा को झटका लगे।' रंजीत ठाकुर (सुप्रा) में इस न्यायालय की टिप्पणियों का भी अपीलकर्ता के लिए कोई फायदा नहीं है। अपीलार्थी के साथ कोई घोर अन्याय तो दूर कोई अन्याय भी नहीं हुआ है।

37. हमें अपील में कोई योग्यता नजर नहीं आती और इसे खारिज किया जाता है।

बी.बी.बी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री सिद्धान्त सक्सेना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>**अस्वीकरण**</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****